



लोक प्रशासन में
उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार
**Prime Minister's Awards for
Excellence in Public Administration**

2013 - 2014

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
भारत सरकार

Department of Administrative Reforms and Public Grievances
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Government of India

विषय-सूची

वर्ष 2013-14 के लिए पुरस्कार विजेता

- 1) 'गर्भाशय बचाओ' : समस्तीपुर, बिहार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्यान्वयन में कदाचार को समाप्त करने की एक पहल 1-3
 - 2) संवेदना अभियान, वलसाड और वापी, गुजरात 4-5
 - 3) "जश्ने जम्हूरियत" : रियासी - लोकतंत्र का उत्सव 6-7
 - 4) सरगुजा फुलवारी पहल, छत्तीसगढ़ 8-10
 - 5) ससुर खदेड़ी-2 एवं इसके उदगम ठिठौरा झील का पुनरुद्धार, जनपद फतेहपुर, उत्तर प्रदेश 11-12
 - 6) मांडवी प्रखंड में प्रायोगिक ई-आरओआर (सामान्य निवास का ई-रिकार्ड) और सामान्य सेवा केंद्रों के जरिए पश्चिम त्रिपुरा जिले में 'संपूर्ण वित्तीय समावेशन' हासिल करना 13-14
 - 7) लाडो (बाल विवाह के उन्मूलन की एक नवीन पहल) 15-17
 - 8) कौशल विकास कार्यक्रम - जनजातीय युवा की रोजगार क्षमता में वृद्धि करने और आय का स्थायी स्रोत उपलब्ध कराने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना 18-19
 - 9) इरविपेरूर ग्राम पंचायत - स्थानीय स्वशासन की सफल कहानी 20-22
 - 10) नहर उपरीय सौर ऊर्जा संयंत्र - हरित और स्वच्छ ऊर्जा की ओर एक नया कदम 23-24
-
-

CONTENTS

Awardees for the Year 2013-14

- 1) “Saving the Womb” An Initiative to address and redress malpractices in the implementation of RSBY in Samastipur, Bihar 1-3
 - 2) “Emotional Drive Campaign”, Valsad and Vapi, Gujarat 4-5
 - 3) “Jashn-e-Jamhuriat” : Reasi-Celebrating Democracy 6-7
 - 4) “Surguja Fulwari Initiative”, Chhattisgarh 8-10
 - 5) Revival of Sasur Khaderi -2 Rivulet and its Origin Thithora Lake in Distt. Fatehpur, U.P. 11-12
 - 6) Achieving ‘Total Financial Inclusion’ in West Tripura district through e-ROR 13-14
 - 7) LADO (An innovative initiative for eradicating child marriages) 15-17
 - 8) Skill Development Program to impart vocational “ training to the tribal youth, Gadchiroli, Maharashtra 18-19
 - 9) Eraviperoor Grama Panchayat - Success Story of Local Self Governance 20-22
 - 10) Canal Top Solar Power Plant-A New Direction to Green and Clean Energy 23-24
-
-

पहल का नाम - 'गर्भाशय बचाओ' : समस्तीपुर, बिहार में
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्यान्वयन
में कदाचार को समाप्त करने की एक पहल

पुरस्कार विजेता का नाम - श्री कुन्दन कुमार, भा.प्र.से., जिला
मजिस्ट्रेट, समस्तीपुर, बिहार

परियोजना संक्षेप में :

इस परियोजना का लक्ष्य बिहार के समस्तीपुर जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के कार्यान्वयन में कदाचार को समाप्त करना है। जिले में गर्भाशयोच्छेदन की अत्यंत उच्च प्रतिशतता (61%) चिंता का कारण थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में चल रहे कदाचार के आरोपों की जांच करने के लिए एक विस्तृत और वैज्ञानिक जांच की गई जो जिला प्रशासन द्वारा स्वतंत्र रूप से इस प्रकार का पहला कार्य था। इसके परिणामस्वरूप शीघ्र धन अर्जित करने के लिए गर्भाशय को अवांछित रूप से निकाल कर भोली-भाली ग्रामीण महिलाओं के साथ धोखा करके उनका शारीरिक और मानसिक शोषण किए जाने का पता चला।

विशेषताएं

- निजी अस्पतालों द्वारा ग्रामीण महिलाओं अधिकांशतः प्रजनन आयु समूह, के कथित शोषण संबंधी लोक शिकायतों पर कार्रवाई की गई।
- प्रत्येक लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए विभिन्न स्तरों पर बहु-स्तरीय टीमों का सृजन
- डाक्टरों और प्रशासकों की टीमों द्वारा विस्तृत मामला दर मामला जांच
- 2606 महिलाओं की चिकित्सा जांच करने हेतु जिला स्तरीय चिकित्सा कैंप
- सभी दोषी अस्पतालों के विरुद्ध कानूनी और निर्णायक कार्रवाई

Name of the Initiative - “Saving the Womb” An Initiative to address and redress malpractices in the implementation of RSBY in Samastipur, Bihar

Name of the Awardee - Shri Kundan Kumar, IAS, District Magistrate, Samastipur, Bihar

Project in Brief:

The project aimed to address and redress malpractices in the implementation of Rashtriya Swastha Bima Yojana (RSBY) in Samastipur district of Bihar. An alarmingly high percentage (61%) of hysterectomies in the district was a cause of concern. A detailed and scientific inquiry- first of its kind conducted independently by the District Administration- was undertaken to investigate allegations of malpractices in the implementation of RSBY. This led to revelation of physical and mental exploitation of gullible rural women by cheating them into unwanted uterus removal surgeries to make quick money.

Highlights

- Acted on public grievances raised by rural women, mostly in the reproductive age group, about alleged exploitation by private hospitals.
- Creation of multi- tier teams at various levels to reach out to each of the beneficiaries involved.
- Detailed case by case inquiry by teams of doctors and administrators.
- District level medical camp to conduct a medical inquiry on 2606 women
- Legal and definitive action against all defaulting hospitals.

प्रभाव

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में चल रही गंभीर प्रकृति के कदाचार के संबंध में ग्रामीण महिलाओं से अनेक शिकायतें प्राप्त हुईं जो विशेषकर जिलों के मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों द्वारा लाभार्थियों के स्मार्ट कार्ड से अधिकाधिक रूप से प्राप्त करने के लिए अवांछित शल्य-क्रिया (जैसेकि गर्भाशयोच्छेदन, एपेंडिक्स निकालना, अंडाशय को निकालना) से संबंधित थी।
- नामिति ने पांच हजार से अधिक लाभार्थियों से संपर्क करते हुए चिकित्सीय-विधि जांच पड़ताल शुरू की। इस चिकित्सीय-विधि जांच-पड़ताल में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल थे :- पांच दिवसीय चिकित्सा कैम्प, पीड़ितों की बंद कमरे में सुनवाई, हजारों पृष्ठों के रिकार्डों का प्रलेखन, दोषी अस्पतालों के विरुद्ध न्यायिक-वत् कार्यवाही करना जिसके फलस्वरूप अस्पतालों को सूची से हटाकर तथा उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। चिकित्सा कैम्प ने एक मंच उपलब्ध कराया जिसमें हजारों पीड़ितों की चिकित्सा जांच की गई और उनकी शिकायतों को रिकार्ड किया गया।
- इस पहल ने इन ग्रामीण महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक कल्याण स्कीमों की आड़ में ऐसे कदाचार के संबंध उनकी संवेदनशीलता के बारे में काफी जागरूकता उत्पन्न की। इसके फलस्वरूप इस स्कीम के बारे में न केवल समस्तीपुर जिले के बीपील के अंतर्गत आने वाले 5.5 लाख परिवारों में बल्कि संपूर्ण भारत में व्यापक जानकारी और जागरूकता उत्पन्न हुई।
- इस पहल के परिणामस्वरूप जिला मजिस्ट्रेटों को उनके जिलों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्यान्वयन की इसी प्रकार जांच-पड़ताल करने के अनुदेश जारी किए गए।
- भारत सरकार ने 40 वर्ष से कम आयु की महिलाओं के गर्भाशयोच्छेदन के लिए पूर्व प्राधिकार को अनिवार्य बनाया। इस पहल के फलस्वरूप पूरे राज्य में हो रहे गर्भाशयोच्छेदन पर रोक लगी।
- भारत सरकार ने अस्पतालों के सूचीबद्ध में श्रेणीकरण की शुरुआत की ताकि मानक भौतिक एवं मानव संसाधन युक्त अस्पतालों को छांटा जा सके। इस स्कीम के अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्रों को सूचीबद्ध करने के

Impact:

- A large number of complaints were received from the rural women regarding malpractices of serious nature in the implementation of RSBY, especially unwarranted surgical procedures (like hysterectomy, appendectomy, oophorectomy etc) for swiping maximum money from the smart card of the beneficiaries by the accredited private clinics of the district.
- The nominee initiated a medico legal investigation by reaching out to more than five thousand beneficiaries. The medico legal investigation included inter alia a five day medical camp, in camera hearing of victims, documentation of records running into thousands of pages, a quasi judicial proceeding against erring clinics leading to de-empanelment of clinics and lodging of FIR against them. The medical camp provided a forum where thousands of victims underwent medical examination and their grievances were recorded.
- The initiative created a lot of awareness about reproductive health care of these rural women and their vulnerability to such malpractices in the guise of social welfare schemes. It led to greater sensitisation and awareness about the scheme not only among the 5.5 lakh families living under BPL of Samastipur district but in the entire country.
- As a result of this initiative, instructions were issued to the DMs of the state to carry out similar investigations in implementation of RSBY in their districts.
- Government of India made pre-authorization mandatory for hysterectomy of women below 40 yrs of age. The initiative led to a check in the wanton hysterectomy taking place across state.
- Government of India introduced the categorization clause in the empanelment of hospitals to weed out clinics with substandard physical and human resources. The approval of the District Core Committee headed by the District Magistrate was made

लिए जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला कोर समिति के अनुमोदन को अनिवार्य बनाया गया।

- सरकारी अस्पतालों को सूचीबद्ध करके लाभार्थियों को एक विश्वसनीय विकल्प उपलब्ध कराया गया। सरकारी अस्पतालों को सूचीबद्ध करने से अस्पतालों की ओर निधि का प्रवाह हुआ जिसका उपयोग अवसंरचना का उन्नयन करने तथा सरकारी तंत्र के डाक्टरों और पराचिकित्सीय स्टाफ को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया।
- इस पहल के पश्चात् बीमा सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रीमियम बोली में तेज गिरावट देखी गई जिसका आशय यह है कि राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों के काफी धन की बचत हुई।

mandatory for the empanelment of health facilities under the scheme.

- The empanelment of public hospitals provided a credible alternative to the beneficiary. The empanelment of public hospitals led to flow of fund to the hospitals which was used for up gradation of infrastructure and incentivising the doctors and paramedical of the govt system.
- The premium bid by the insurance providers after the initiative saw steep decline which meant saving of huge money for both the State government and the Government of India.

पहल का नाम - संवेदना अभियान, वलसाड और वापी, गुजरात

पुरस्कार विजेता का नाम - डा. विक्रान्त पाण्डेय, भा.प्र.से., कलेक्टर
एवं जिला मजिस्ट्रेट, वलसाड, गुजरात

परियोजना संक्षेप में

वलसाड एक जनजातीय जिला है जिसके दो तालुका - कपर्दा और धर्मपुर अत्यंत पिछड़े क्षेत्र हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की 55% आबादी जनजातीय और 2.6% आबादी अनुसूचित जाति से संबंधित है। जिले की बीपीएल आबादी 37% है। वर्ष 2006 - वन अधिकार अधिनियम के बाद से जिले में वन भूमि प्रयोक्ता अधिकार के अधिकांश मामले लंबित थे। इस अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित तीन श्रेणियों में कार्रवाई की गई :-

- वन भूमि प्रयोक्ता अधिकार
- सामाजिक सुरक्षा स्कीम
- विकलांगों के लिए परिचय सम्मेलन

विशेषताएं

पारदर्शिता और स्टेकहोल्डर भागीदारी

सभी लाभार्थी वन भूमि प्रयोक्ता अधिकार प्राप्त करने हेतु स्थल पर मौजूद थे तथा माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में उसी समय एक ही स्थान पर प्रमाणपत्र वितरित किए गए।

सरकारी तंत्र से लाल फीताशाही को समाप्त किया गया तथा अल्प समयावधि में लाभ प्रदान किए गए।

पहल की नवीनता और इसकी अनुकरणीयता

वन अधिकार अधिनियम के सभी मामले जो वर्षों से लंबित थे उनका सफलतापूर्वक निपटान किया गया और भूमि आवंटित की गई।

सभी लाभार्थियों को एकल स्थल के आधार पर प्रदायगी की गई। एक विशाल "विकलांग व्यक्तियों (बधिर, मूक और नेत्रहीन) के लिए परिचय सम्मेलन" वापी में आयोजित किया गया। 'संवेदना अभियान' से लोग सीधे ही सरकार से जुड़े फलस्वरूप आंदोलनों और धरनों की संख्या कम हुई।

Name of the Initiative - “Emotional Drive Campaign”,
Valsad and Vapi, Gujarat

Name of the Awardee - Dr. Vikrant Pandey, IAS, Collector and
District Magistrate, Valsad, Gujarat

Project in Brief

Valsad is a tribal district where two Talukas- Kaprada and Dharampur are quite backward. As per 2011 census, 55% of District population is tribal and 2.6% is schedule caste. BPL population of district is 37%. After 2006-Forest Right Act, a large number of user rights of forest land cases were pending in the District. Under the campaign, the following three categories of action were taken.

- User rights of forest Land
- Social Security Schemes
- Parichay Sammelan for differently abled

Highlights

Transparency and stake holder participation

All beneficiaries were present at the site to receive the user rights of forestland and Certificates were distributed at a single location at the same time in the presence of Hon’ble Chief Minister.

Red tapism from the system was eliminated and in a small time period the benefits were delivered.

Innovativeness of the initiative and its replicability

All the cases of FRA which were pending since long years have been successfully cleared and land allotted.

Delivery was done to all beneficiaries based on a single site. The largest “Parichay Sammelan for differently-abled” (deaf, dumb and blind) was held at Vapi. With “Emotional Drive Campaign” people connected directly with the government resulting in less number of Andolans and Dharnas.

प्रभाव

सरकार के सभी लाभार्थी कार्यक्रमों के संबंध में प्रशासन में पारदर्शिता आई। लालफीताशाही समाप्त हुई तथा सरकार और जनता के बीच अंतराल कम हुआ। कृषि और उद्यान विभाग द्वारा वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि प्रयोक्ता अधिकार प्राप्त करने वाले जनजातीय व्यक्तियों के लिए भूमि आयोजना की गई। इससे जनजातीय किसानों की उत्पादकता में वृद्धि हुई तथा जनजातीय व्यक्तियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में बदलाव आया। वे अब सरकार से व्यक्तिगत और चिकित्सीय लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। वन भूमि प्रयोक्ता अधिकार छोटे और सीमांत किसानों के लिए एकबारगी जीवन परिवर्तन करने वाली घटना है। इस संसाधन के आधार पर वे अब अपनी आजीविका सृजित करने में सक्षम हैं, अन्य संसाधनों का निर्माण कर सकते हैं और अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकते हैं।

इस पहल के फलस्वरूप सेवाओं की प्रदायगी समय में सुधार हुआ तथा परिणामस्वरूप लाभार्थियों से बेहतर फीडबैक प्राप्त हुए। मापनीय संकेतकों के सुधार और सरलीकृत प्रक्रियाएं अन्य महत्वपूर्ण परिणाम हैं।

Impact

Transparency was achieved in administration for all beneficiary programs of government. Red-tapism was removed, thus narrowing the gap between government and public. Land planning was done by Agriculture and Horticulture Department for tribal people who got user rights of forest land under FRA. It has increased the productivity of tribal farmers and made difference in socio-economic conditions of tribal people. They now also get personal and medical benefits from the government. Land user rights of forests is a onetime, life changing event for small and marginal farmers. Based on this resource they are now able to generate livelihood, raise other resources and support their family members.

The initiative led to improvement in delivery time of services and resulted in better feedback from beneficiaries. Improvement in measurable indicators and simplified procedures were other important outcomes.

पहल का नाम - "जश्ने जम्हूरियत" : रियासी - लोकतंत्र का उत्सव
(अलगाव का सामना करने तथा समावेशी चुनाव
साक्षरता और भागीदारी में वृद्धि करने के लिए
चुनाव परियोजना)

पुरस्कार विजेता का नाम : डा. शाहिद इकबाल चौधरी, भा.प्र.से., जिला
कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/ जिला विकास
आयुक्त रियासी (अब जिला कलेक्टर, कटुआ)

परियोजना संक्षेप में

रियासी जिला उन 12 जिलों में से है जहां परम्परागत रूप से चुनाव में बहुत कम मतदान होता है। वर्ष 2009 के लोक सभा चुनाव में जिले में 43% का निराशाजनक मतदान दर्ज किया गया जिसमें अत्यंत कम 23% घूमंतू और लगभग 33% महिलाओं की भागीदारी थी। जिला कलेक्टर/उपायुक्त द्वारा सभी 3,35,000 मतदाताओं से संपर्क करने, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए चुनाव का बहिष्कार करने वाले को समझाने, विकलांग मतदाताओं की पहचान करने तथा उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने, महिलाओं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति की न्यूनतम भागीदारी वाले मतदान केंद्रों की पहचान करने के लिए एक परियोजना शुरू की गई तथा इस परियोजना के अंतर्गत उनकी भागीदारी के लिए वैज्ञानिक अभियान आयोजित किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत 35 से अधिक अभियान और 105 कार्यकलाप शुरू किए गए तथा इस अभियान के प्रायोजक के रूप में 85 भागीदार संगठन आगे आए।

विशेषताएं

- गांव/मतदान केंद्र स्तर पर टीम और अवसंरचना की स्थापना
- दीर्घकालिक पहल के लिए भागीदारी बनाना : 85 संगठन
- स्कूलों के लिए विशेष कार्यक्रम
- चुनाव ग्राम सभा : जमीनी लोकतंत्र का पुनर्जन्म
- मतदाता नामांकन : मिशन मोड दृष्टिकोण

Name of the Initiative - “Jashn-e-Jamhuriat” : Reasi-Celebrating Democracy (Election Project for combating alienation and increasing inclusive electoral literacy & participation)

Name of the Awardee - Dr. Shahid Iqbal Choudhary, IAS,
District Collector / District Magistrate/
Distt Development Commissioner
Reasi

Project in Brief

District Reasi was among 12 districts having traditionally low turnout in elections. The district recorded a dismal 43% in 2009 Lok Sabha election with participation of nomads meagre 23% and women around 33%. A project was launched by District Collector / Deputy Commissioner for reaching out to all 3,35,000 voters, convincing poll boycotters to participate in democratic exercise, identify differently-abled voters and facilitate their participation, identify the polling booth with lowest participation of women, STs, SCs and organizing scientific campaign under the project for their participation. More than 35 campaigns and 105 activities were launched under the project and 85 partner organisations roped in for sponsorship of campaigns.

Highlights:

- Establishment of Teams and Infrastructure at village / booth level
- Building Partnership for Sustainable Initiative: 85 Organizations
- Special Programme for Schools
- Electoral Gram Sabhas : Reinventing Grassroots democracy
- Voter Enrolment: Mission Mode Approach

- हरित मत वृक्षारोपण अभियान : पर्यावरण और लोकतंत्र - एक पौधा, एक मतदाता
- "जिरगा" घूमंतू मतदाताओं के नामांकन और उनकी भागीदारी के लिए मिशन
- किसानों के चुनाव नामांकन/भागीदारी के लिए जय किसान, जय हिंदुस्तान अभियान
- महिलाओं का नामांकन और उनकी भागीदारी
- चुनाव भागीदारी हेतु राष्ट्र के लिए कुश्ती और खेल अभियान
- लोकतंत्र रक्त दान कैम्प
- चुनाव फोटो प्रदर्शनी
- नुक्कड़ नाटक और कार्यक्रम
- विकलांगों, वृद्धों और अशक्त मतदाताओं के समावेशन के लिए 'रहबर' स्कीम
- स्टाम्पस : घर तक पहुंच - दस्तावेजों पर चुनाव भागीदारी हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी का संदेश
- भाषा : जागरूकता मिशन
- युवा संसद : युवाओं को जोड़ना
- पत्रों, एसएमएस, पोस्ट कार्डों के जरिए अभियान
- मतदान केंद्र अभियान
- मतदान केंद्र गोद लेना : "अपना बूथ अभियान"
- समावेशन हेतु पहचान किए गए मतदान केंद्रों के लिए लक्षित अभियान

प्रभाव

इसके परिणामस्वरूप इस आतंकवाद पीड़ित पहाड़ी जिले में मतदान का एक राष्ट्रीय रिकार्ड बना जिसमें मतदान 43% से बढ़कर 81% तक हुआ, महिलाओं की भागीदारी 33% बढ़कर 79% हुई, घूमंतूओं की भागीदारी 23% बढ़कर 80% हुई (घूमंतूओं के प्रवास में 1 महीने का विलंब हुआ) तथा जिले में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए 301 मतदान केन्द्र क्षेत्र टीमों की एक स्थायी ढांचे की स्थापना हुई। भारत निर्वाचन आयोग ने इस परियोजना को देश में दोहराए जाने योग्य उदाहरण के तौर पर इसे विशिष्ट और असाधारण परियोजना का दर्जा प्रदान किया।

- Green Vote Plantation Drive: Environment & Democracy-“One Sapling for one Voter
- “JIRGA”: Mission for Enrolment of Nomadic Voters and their Participation
- Jai Kisan Jai Hindustan campaign for Electoral Enrolment/ Participation of Farmers
- Women Enrolment and Participation
- Wrestling for Nation and Sports Campaign for Electoral Participation
- Democracy Blood Donation Camps
- Electoral Photo Exhibition
- Street Plays and Shows
- “Rehbar” scheme for inclusion of specially abled, aged and infirmed voters.
- Stamps: Reaching homes - DEO’s message for electoral participation on documents:
- Language: Awareness Mission
- Youth Parliament: Linking Youth
- Campaign through Letters, SMS, Post-Cards
- Polling Booth Campaigns
- Polling Station Adoption : “Apna Booth Campaign”
- Targeted Campaign for Identified Polling Booths for Inclusion

Impact

The results in this militancy infested district are a national record, with turn out increasing from 43% to 81%, women participation 79% up from 33%, participation of nomads up from 23% to 80% and setting up of permanent structure of 301 Polling Booth Area Teams to strengthen democracy in district. Election Commission of India has rated the project as exceptional and extraordinary, as an example for country for replication.

पहल का नाम - सरगुजा फुलवारी पहल, छत्तीसगढ़

पुरस्कार विजेता - श्री आर. प्रसन्ना, कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़

परियोजना संक्षेप में

एकीकृत बाल विकास स्कीम (आईसीडीएस) पोषण संबंधी एक मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम है। तथापि इसके संसाधनों को 3-6 वर्ष के आयु समूह के बच्चों पर अधिक केंद्रित किया जाता है। गर्भवती महिलाओं और 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए आईसीडीएस में मुख्यतः राशन घर ले जाओ (टीएचआर) की व्यवस्था है जो पोषक विविधता और दिवस देखभाल के अंतराल को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

कुपोषण की सतत चुनौती का सामना करने के लिए 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं की जरूरतों को पूरा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरगुजा फुलवारी पहल फुलवारी नामक समुदाय प्रबंधित बाल पोषण और दिवस देखभाल केंद्र की स्थापना करने का एक नवप्रवर्तन है ताकि 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बीच कुपोषण का निराकरण करने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।

विशेषताएं

- फुलवारी केंद्र शुरू करने के लिए अत्यंत अभाव ग्रस्त तथा कुपोषित जनजातीय निवास स्थानों को प्राथमिकता दी गई। इनमें से, ऐसे निवास स्थान जहां स्थानीय समुदाय बाल देखभाल हेतु स्वैच्छिक समय का योगदान करके फुलवारी केंद्र संचालित करने हेतु कृत संकल्प थे, उनका अंतिम रूप से चयन किया गया। ग्राम पंचायतों तथा मितानी नामक सामुदायिक स्वास्थ्य वर्करों ने समुदायों को संगठित करने के लिए मिलकर कार्य किया। जिला पंचायतों ने प्रत्येक चयनित निवास स्थान में फुलवारी केंद्र संचालित करने हेतु माता समूह को अनुदान (50,000/- रूपए प्रति वर्ष) प्रदान किया।

Name of the Initiative - “Surguja Fulwari Initiative”, Chhattisgarh

Name of the Awardee - Shri R. Prasana, Collector & District
Magistrate, District Surguja, Chhattisgarh

Project in brief

Integrated Child Development Scheme (ICDS) is the main national programme on nutrition. Its resources, however, are focused more on children in the age group 3-6 years. For the pregnant women and under-3 year children, ICDS mainly provides Take Home Rations (THR) which is not adequate to address the gaps in dietary diversity and day care.

Addressing the needs of under-3 year children and pregnant women is of crucial importance while tackling the persistent challenge of malnutrition. Surguja Fulwari Initiative is an innovation to set up Community managed Child Nutrition cum Day Care centers called Fulwaris to focus on addressing malnutrition among under-3 children.

Implementation Highlights

- Tribal habitations with higher levels of deprivation and malnutrition were prioritized for starting Fulwari centers. Out of these, habitations where the local community resolved to run a Fulwari centre by contributing voluntary time for child care were finally selected. Gram Panchayats and Community Health Workers called Mitanins worked together for mobilizing the communities. The Zila Panchayat provided a grant (average Rs.50,000 p.a.) to mothers’ group in each selected habitation to run the Fulwari.

- फुलवारी सप्ताह के 7 दिन में प्रत्येक दिन 7 घंटे के लिए खुला रहता है। 6 माह से 3 वर्ष की आयु के बच्चों तथा गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं फुलवारी केंद्र में आती हैं तथा प्रतिदिन तीन बार गर्म भोजन का आनंद लेती हैं। फुलवारी के भोजन में कतिपय मुख्य संघटक अंडे, हरी सब्जी और वसा हैं। प्रतिदिन दो माताएं खाना पकाने का समय स्वैच्छिक रूप से देती हैं तथा फुलवारी में बच्चों की देखभाल करती हैं। समुदाय के किसी इच्छुक सदस्य द्वारा स्वैच्छिक रूप से स्थान के लिए योगदान दिया जाता है। जिला पंचायत से प्राप्त अनुदान का उपयोग मुख्यतः माता समूह द्वारा फुलवारी के लिए राशन और हरी सब्जियां खरीदने में किया जाता है। माताएं फुलवारी के संचालन में अपनी सक्रिय भागदारी के जरिए बाल भोजन तथा साफ-सफाई के बारे में भी सीखती हैं। माताओं को उनके वासभूमि पर किचन गार्डन, मुर्गी पालन, फलदार वृक्ष आदि लगाने के लिए प्रोत्साहित और प्रशिक्षित भी किया जाता है।
- फुलकारी एक नवीन पहल है जिसमें किसी नए वर्कर की नियुक्ति नहीं की जाती और न ही किसी नए अवसंरचना की जरूरत होती है लेकिन फिर भी यह छोटे बच्चों को पोषण और दिन में देखभाल की सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्षम है। यह एक स्थायी मॉडल है जो सरकारी धनराशि को सीधे ही बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं पर व्यय करता है और वर्करों को कोई भुगतान भी नहीं करना पड़ता। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि फुलवारी को आरंभ करने के लिए किसी पूर्व तैयारी अवधि की जरूरत नहीं होती क्योंकि इसमें कोई नियुक्ति (स्टाफ) अथवा निर्माण (भवन) शामिल नहीं हैं।

प्रभाव

माता समूह ने अपने स्वैच्छिक प्रयासों से अब लगभग एक वर्ष के लिए लगभग 300 फुलवारी केंद्र के परिचालन का प्रबंध किया है। इस परियोजना से लगभग 3500 बच्चे तथा 600 गर्भवती महिलाएं लाभान्वित हुईं। यह पहल कुपोषण को समाप्त करने में पंचायतों की सहभागिता कराने में सफल रही।

- The Fulwari stays open for 7 hours a day, 7 days a week. Children aged 6 months - 3 years and pregnant and lactating women come to Fulwari and receive three hot cooked meals daily. Eggs, green vegetables and oil form some of the key components of food in the Fulwari. Everyday two of the mothers volunteer their time to cook and take care of children in the Fulwari. The space is contributed voluntarily by any willing member of the community. The grant from Zila Panchayat is mainly used by mothers' group for buying ration and vegetables for the Fulwari. Mothers by their active involvement in running the Fulwari also learn more on child feeding and hygiene. Mothers are also encouraged and trained to grow kitchen gardens, backyard poultry, fruit trees etc. in their homesteads.
- Fulwari is an innovative initiative which does not appoint any new worker nor does it need any new infrastructure and yet is able to provide nutrition and daycare services for young children. It is a sustainable model which spends Government funds directly on food for children and pregnant women and not on paying more workers. The biggest advantage is that there is hardly any gestation period in starting the Fulwari since no recruitment (of staff) or construction (of building) is involved.

Impact:

Mothers' groups have managed to run close to 300 Fulwari centres for almost a year now with their voluntary efforts. Around 3,500 children and 600 pregnant women have benefited from the project. The initiative has succeeded in involving Panchayats in addressing malnutrition. The knowledge of mothers has also improved in terms of child-care practices.

बाल देखभाल व्यवहारों के संबंध में माताओं के ज्ञान में वृद्धि हुई। बाल कुपोषण, रूगण्ता तथा मृत्यु के मापनीय संकेतकों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई।

यह पहल सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देने के तंत्र के रूप में भी सफल रही क्योंकि समुदाय अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए एक साथ आगे आए। इससे लैंगिक भेदभाव में कमी आई। माताएं उपार्जन अवसरों (जैसे मनरेगा कार्य) में भाग लेने में सक्षम होती हैं क्योंकि फुलवारी बाल देखभाल के केंद्र के रूप में कार्य करती है। फुलवारी ने अस्पृश्यता की कुप्रथा को भी नियंत्रित किया। फुलवारी केंद्रों में सभी जातियों के बच्चे तथा गर्भवती महिलाएं एक साथ खाना खाते हैं।

Category - Individual

A significant drop in measurable indicators of child malnutrition, morbidity and mortality has been recorded.

The initiative has also succeeded as a mechanism for promoting social cohesion as community comes together for taking care of its children. It has reduced gender discrimination. Mothers are able to participate in earning opportunities (like MNREGS work) as Fulwari serves as a collective for childcare. Fulwari has also taken the practice of untouchability head-on. Children and pregnant women from all castes eat together at the Fulwari.

पहल का नाम : ससुर खदेड़ी-2 एवं इसके उदगम ठिठौरा झील का पुनरुद्धार, जनपद फतेहपुर, उत्तर प्रदेश

पुरस्कार विजेताओं का नाम :

1. श्रीमती कंचन वर्मा, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार
2. श्री हरीश चंद्र प्रसाद
3. श्री कप्तान सिंह
4. श्री अरविंद कुमार

परियोजना संक्षेप में :

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत फतेहपुर जिले में 46 कि.मी. लम्बी **ससुर खदेड़ी-2** नदी के 38 कि.मी. हिस्से और इसके उदगम स्थान **ठिठौरा झील** का पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार किया गया जिसमें रिकार्ड 45 दिनों में 2,04,900 श्रम दिवसों का सृजन करते हुए दो मृतप्रायः जल स्रोतों को जीवनदान दिया गया।

यह पहल ससुर खदेरी-2 के पुनरुद्धार, मरम्मत और प्रवाह को पुनः बहाल करके शुष्क मौसम में जल की भारी कमी और वर्षा के दौरान जल भराव की समस्या का निराकरण करने के लिए की गई थी। इससे 7.377 हेक्टेयर क्षेत्र में जल भंडारण की क्षमता का पुनर्निर्माण हुआ तथा भूमिगत जल पुनर्भरण में सुधार के साथ वर्षा के दौरान बाढ़ का जोखिम भी कम हुआ। साथ ही इसका लक्ष्य जमीन को क्षारीय और बंजर होने से बचाना था।

विशेषताएं

- अत्यंत कुशल योजना
- अभिसारिता दृष्टिकोण
- क्यूनेट मॉडल
- इसे जनता की परियोजना बनाना
- परिणाम को अधिकतम सीमा तक बढ़ाना

Name of the initiative – **Revival of Sasur Khaderi -2 Rivulet and its Origin Thithora Lake in Distt. Fatehpur, U.P.**

Name of the Awardees –

1. Ms Kanchan Verma, Special Secretary, Government of UP
2. Mr. Harish Chandra, District Development Officer
3. Mr. Kaptan Singh, Executive Engineer
4. Mr. Arvind Kumar, Executive Engineer

Project in Brief

38 Km. Stretch of 46 km. long river **Sasur Khaderi – 2** and its origin **Thithora Lake** in district Fatehpur were recreated and rejuvenated under MNREGS generating 2,04,900 man-days of employment in record 45 days and the twin dead water bodies were brought back to life.

The initiative sought to tackle acute water crisis in dry season and problem of water logging during rains by way of revival, restoration and rejuvenation of the rivulet. It recreated water storage capacity in an area of 7.377 hectare and also improved ground water recharge together with flood mitigation during rains. At the same time it aims at preventing the soil from turning sodic and infertile.

Highlights

- Meticulous planning
- Convergence approach
- Qunet Model
- Making it a People’s project
- Maximizing the output

- श्रम का संरक्षण करना
- गहन निगरानी

प्रभाव

- **जलीय पैरामीटर** - इस पहल के पश्चात् जल बहाव 16, जुलाई 2013 को 689.95 क्यूसेक मापा गया जबकि पिछले वर्ष यह लगभग शून्य था। इसी प्रकार 15 जून, 2013 को झील का स्थिर भंडार लगभग 15000 क्यूमेक मापा गया था।
- **रोजगार सृजन** - 45 दिनों में 2,04,900 श्रम दिवसों का सृजन गया गया जिससे जिले में प्रतिवर्ष कार्य दिवस का औसत 30 से बढ़कर 90 तक हो गया।
- **बाढ़ और जल भराव में कमी** - वर्ष 2013 में भारी वर्षा के दौरान जल स्रोतों के जलग्रहण क्षेत्र में कोई जल भराव नहीं हुआ जबकि पिछले वर्षों में ऐसी स्थिति में यह एक आम बात थी।
- **पर्यावरण में सुधार** - झील की सीमा और नदी के किनारों पर वृक्षारोपण किया गया जिससे क्षेत्र के पर्यावरण की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। जल भराव के कारण जमीन को क्षारीय एवं बंजर बन जाने से बचाया जा सकेगा। झील विविध वनस्पति एवं जीव जंतुओं को प्राकृतिक वास उपलब्ध कराएगा और प्रवासी पक्षियों के लिए एक गतंव्य स्थल उपलब्ध कराएगा।

- Care for the labour
- Close monitoring

Impact:

- **Hydraulic parameters** –Post Initiative discharge on July 16, 2013 was measured as 689.95 cusecs compared to almost **nil** in the previous years. Similarly dead storage in the lake on June 15, 2013 was measured approximately 15000 cum.
- **Employment generation** – 2,04,900 person-days generated in 45 days raising the district average from 30 to 90 man-days per year.
- **Mitigation of floods and water logging** – No water logging occurred in catchment areas of the water bodies in heavy rainfall of 2013 which was a common feature in previous years in similar situations.
- **Improvement in environment** – Plantation done on lake boundary and rivulet banks will add to the environmental quotient of the area. Soil will be saved from turning sodic and infertile due to water logging. Lake site will provide a habitat for diverse flora and fauna and a destination for migratory birds.

पहल का नाम - मांडवी प्रखंड में प्रायोगिक ई-आरओआर
(सामान्य निवास का ई-रिकार्ड) और सामान्य
सेवा केंद्रों के जरिए पश्चिम त्रिपुरा जिले में
'संपूर्ण वित्तीय समावेशन' हासिल करना

पुरस्कार विजेताओं के नाम - (1) श्री अभिषेक सिंह, भा.प्र.से., जिला
मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर, त्रिपुरा
(2) श्री गित्ते किरण कुमार दिनकर राव
(3) श्री प्रमोद कुमार पाल
(4) श्री मनोहर विश्वास
(5) श्री प्रदीप राय

परियोजना संक्षेप में

पश्चिम त्रिपुरा जिले में संपूर्ण वित्तीय समावेशन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बैंकों, सामान्य सेवा केंद्रों, पीआरआई और एनआईसी के समन्वय से जनजातीय बहुल मांडवी प्रखंड में एक पहल शुरू की गई जिसमें ई-आरओआर (सामान्य निवास का ई-रिकार्ड) के अनुसार कवर नहीं किए गए परिवारों का पता लगाकर उनकी पहचान की गई तथा उन्हें वास्तविक शाखाओं और दूरदराज के क्षेत्रों में शाखा रहित बैंकिंग (सीएससी/यूएसबी) के जरिए बैंकिंग सुविधाओं के अंतर्गत लाया गया। सीबीएस खाता के साथ 100% कवरेज प्राप्त कर लिया गया है तथा अब अधिकांश लाभ बैंक खाता के जरिए ही दिए जा रहे हैं। यह पहल अन्य प्रखंडों में और वर्ष 2014-15 में भी दोहरायी जा रही है।

विशेषताएं

- सीबीएस खाता के साथ सभी परिवारों का 100% कवरेज
- 4 सामान्य सेवा केंद्र (यूएसबी) और 2 एटीएम खोलना। पूरे जिले में 20 यूएसबी।
- ई-आरओआर में खाता को संबद्ध करना और डाटाबेस का रख-रखाव

Name of the Initiative - **Achieving ‘Total Financial Inclusion’ in West Tripura district through e-ROR (e-Record of Ordinary Residence) & Common Service Centers piloted at Mandwi block.**

Name of the Awardees –

- (1) Shri Abhishek Singh, IAS, Distt Magistrate & Collector, Tripura
- (2) Shir Gitte Kiran Kumar Dinkarrao
- (3) Shri Pramod Kumar Pal
- (4) Shri Manohar Bishwas
- (5) Shri Pradip Roy

Project in Brief

To achieve Total Financial Inclusion in West Tripura district, an initiative was launched in Tribal dominated Mandwi block in coordination with Banks, Common Services Centers, PRIs & NIC through tracking & identifying uncovered families as per eROR (e-Record of Ordinary Residence) and bringing them under banking facilities through brick & mortar branches & Branchless banking (CSCs/ USBs) in remote areas. 100% coverage has been achieved with CBS accounts & most of the benefits are now routed through the Bank accounts only. Initiative is being replicated in other blocks as well in the year 2014-15.

Highlights

- 100% coverage of all families with CBS accounts
- Opening of 4 nos. Common Service Centers (USBs) & 2 nos. ATMs. 20 nos. of USBs in entire district.
- Seeding of accounts in the eROR & maintenance of database

- नई बैंक शाखा तथा यूएसबी खोलने के लिए जीआईएस आधारित मानचित्रण
- इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (ईएफएमएस) में रॉल आउट करना
- व्यवसाय अभिकर्ता के जरिए द्वार पर सेवा प्रदायगी
- एमएनआरईजीएस, आईएवाई, एनएसएपी, एनबीए, जेएसवाई, जेएसएसके आदि के तहत भुगतानों जैसे लाभों को जोड़ना
- प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाना

प्रभाव

- सीबीएस खाता के साथ सभी परिवारों को कवर किया गया
- 20 यूएसबी के जरिए शाखा रहित बैंकिंग का विस्तार
- एमएनआरईजीएस, आईएवाई, जेएसवाई आदि के तहत लाभों का इलेक्ट्रॉनिक अंतरण
- 2 वर्षों में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में क्रेडिट में 220% की वृद्धि
- स्कीमों और बैंकों के डाटाबेस में खातों को सम्बद्ध किया गया।
- अक्टूबर/नवम्बर, 2014 तक प्रधानमंत्री जन-धन योजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समुचित प्लेटफार्म।

- GIS based mapping for opening of new bank branches & USBs
- Rolling out of Electronic Fund Management System (EFMS)
- Door step service delivery through Business Correspondents
- Linking of benefits like payment under MNREGS, IAY, NSAP, NBA, JSY, JSSK etc.
- Availing of the credit facilities in priority sectors.

Impact

- All families were covered with CBS bank accounts
- Extension of Branchless banking through 20 nos. USBs
- Electronic transfer of benefits under MNREGS, IAY, JSY etc.
- 220% increase in credit in the Agri & allied sectors in 2 yrs.
- Seeding of the accounts in the databases of Schemes & banks
- Suitable platform to achieve objectives of PMJDY by October / November, 2014.

पहल का नाम - लाडो (बाल विवाह के उन्मूलन की एक नवीन पहल)

- पुरस्कार विजेता का नाम :
- (1) श्री जे.एन. कांसोटिया, भा.प्र.से.,
प्रधान सचिव, मध्य प्रदेश सरकार
 - (2) श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव
 - (3) श्रीमती रेखा शर्मा
 - (4) श्री हरीश खरे
 - (5) श्री अरविंद सिंह भाल
 - (6) श्रीमती टिनी पांडेय
 - (7) श्री सुशील कुमार वर्मा

परियोजना संक्षेप में

लाडो अभियान संचालनालाय महिला सशक्तिकरण, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में बाल विवाह का उन्मूलन करने हेतु एक परिवेश तैयार करने के लिए शुरू की गई है। इसकी अभिकल्पना बाल विवाह के परिणामों के बारे में समुदाय को जानकारी देने और प्रशिक्षित करने की दृष्टि से की गई है। लाडो अभियान के चार निम्नलिखित घटक हैं :-

- समुदाय संवेदनशीलता
- कोर समूह सदस्यों का प्रशिक्षण
- प्रचार अभियान
- बाल विवाह की रोकथाम

विशेषताएं

- बाल विवाह की रोकथाम करने के लिए प्रत्येक गांव/वार्ड में कोर समूह का गठन करना।
- एक सक्षम परिवेश का सृजन करने के लिए समुदाय को संवेदनशील बनाने पर ध्यान केंद्रित करना।
- उन क्षेत्रों और जिलों में ध्यान केंद्रित करना जहां बाल विवाह की घटना बहुत अधिक है।

Name of the Initiative -	LADO (An innovative initiative for eradicating child marriages)
Name of the Awardees –	(1) Shri J.N. Kansotia, IAS, Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh (2) Smt. Kalpana Srivastava (3) Smt. Rekha Sharma (4) Shri Harish Khare (5) Shri Arvind Singh Bhal (6) Smt. Tini Pandey (7) Shri Sushil Kumar Verma

Project in Brief

LADO campaign has been initiated by the Directorate of Women Empowerment, Government of Madhya Pradesh for creating an environment for eradicating child marriages from the state. It is designed with a view to sensitize and train the community about consequences of child marriages. The LADO campaign has the following four components:-

- Community sensitization
- Training of core group members
- Promotional Campaign
- Prevention of Child Marriage

Highlights

- Constitution of a Core Group in each village/ward for prevention of child marriages
- Focus on sensitization of community for creating an enabling environment.
- Focus on those areas and districts where the incidence of child marriages is high.

- कोर समूह सदस्यों की क्षमताओं में वृद्धि करना।
- रेडियो इंकार, टेलीविजन स्काल, स्कूल, टेलीविजन वार्ता कार्यक्रम, फिल्म प्रसारण आदि जैसे श्रव्य-दृश्य संचार के माध्यम से प्रचार अभियान।
- विशिष्ट अभियान हेतु अभिनय करने, नुक्कड़ नाटक जैसे परम्परागत पद्धतियों का उपयोग।
- विज्ञापन के जरिए समाचार पत्रों तथा विज्ञापन बोर्ड, फ्लेक्स, प्रचार आदि अन्य प्रचार-प्रसार पद्धतियों का कारगर उपयोग।
- पहल की सफलता सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त रूप से निगरानी।

प्रभाव

- मात्र एक वर्ष की समयावधि में 40,000 से अधिक कोर समूह का गठन किया गया। इन कोर समूहों की सभी बसे हुए गांव और वार्डों तक पहुंच है।
- एक वर्ष की समयावधि में 80,000 आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए कोर समूह द्वारा कुल 16 लाख लोगों को संवेदनशील बनाया गया।
- कोर समूह द्वारा 12,439 स्कूलों को कवर किया गया जहां बाल विवाह के कुपरिणामों के बारे में बच्चों को अवगत कराने के लिए संवेदी कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- इस पहल से पूर्व मार्च, 2013 तक केवल 181 बाल विवाह कार्यक्रमों को रोका गया था। लाडो अभियान शुरू होने के बाद इस पहल के साथ समुदाय की सहभागिता से बाल विवाह समारोहों की संख्या में उल्लेखनीय कमी हुई। वर्ष 2013-14 में यह 401 थी जो वर्ष 2014-15 के दौरान 4 माह में और बढ़कर 661 तक हो गई।
- यह पाया गया कि जनजातीय जिलों जैसे धार, खांडवा, झाबुआ, विदिशा और सामंती प्रभाव वाले जिले जैसे राजगढ़, रतलाम आदि के समावेश के कारण इंदौर, भोपाल और उज्जैन

- Enhancing capacities of core group members.
- Promotional campaign through audio-visual communication like Radio Jingles, Television scroll, television talk shows, film broadcasting etc.
- Use of traditional methods like role play, nukkad natak for specific campaigning.
- Effective use of print media through advertisement and other methods of dissemination of information like hoardings, flex, publicity etc.
- Concurrent monitoring to ensure success in the initiative.

Impact:

- Over 40,000 Core Groups had been formed in a span of just over one year. These core groups have access to all the populated villages and wards.
- In a span of one year, total 16 lacs people were sensitized by the core group through 80,000 Aanganwadi centres.
- A total of 12,439 Schools were covered by the core group where sensitization programmes for children were conducted for making them aware about consequences of child marriages.
- Prior to the initiative, till March 2013 only 181 child marriage functions were stopped. After initiating the LADO Campaign the number of child marriage functions has decreased remarkably since the involvement of the community with the initiative. In 2013-14, it was 401, which further increased to 661 in 4 months during 2014-15.
- It has been observed that Indore, Bhopal and Ujjain divisions have reported maximum instances of child marriages and its prevention due to the inclusion of tribal districts like Dhar, Khandwa, Jhabua, Vidisha and

उपमंडलों में बाल विवाह और इसके रोकथाम की अधिकतम घटनाओं की रिपोर्ट मिली है।

- बाल अधिकार अधिनियमों के बारे में वर्धित ज्ञान से युक्त 40,000 कोर समूह का निर्माण।
- स्कूली बच्चों को संवेदी बनाने के फलस्वरूप बाल विवाह के प्रति उनकी ओर से सक्रिय प्रतिक्रिया हुई।
- बच्चों के नामांकन और स्कूलों में पढ़ाई जारी रखने की संख्या में वृद्धि हुई।

feudal dominance districts like Rajgarh, Ratlam etc.

- Evolution of 40,000 core groups with enhanced knowledge about child rights acts.
- Sensitization of school children has led to proactive responses from their side towards child marriages.
- Enhanced enrollment of children and their retention in schools.

पहल का नाम : कौशल विकास कार्यक्रम - जनजातीय युवा की रोजगार क्षमता में वृद्धि करने और आय का स्थायी स्रोत उपलब्ध कराने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना

पुरस्कार विजेताओं के नाम :

- (1) श्री रंजीत कुमार, भा.प्र.से., जिला कलेक्टर, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र
- (2) श्री अभिषेक कृष्णा
- (3) श्री टी.एस. के. रेड्डी
- (4) श्री पी.वी. देशमाने
- (5) श्री वाई.एस. शिंदे

परियोजना संक्षेप में

- कौशल विकास संबंधी प्रधानमंत्री के परामर्श के दिशा-निर्देशों के आधार पर व्यापक तौर पर मूल क्षेत्रों पर निर्भर युवकों की रोजगार क्षमता में वृद्धि करने हेतु कौशल विकास कार्यक्रम नामक एक पहल शुरू की गई। जिला कौशल विकास कार्यकारी समिति के नियंत्रणाधीन कार्यक्रम को विनियमित करने के लिए जिले में कैरियर मार्गदर्शन और परामर्श केंद्र का गठन किया गया। जिला कलेक्टर इस समिति के अध्यक्ष हैं।
- बेरोजगार/अल्प रोजगार युवक की ग्राम स्तर पर परामर्श की जाती है जिसके बाद प्रवेश परीक्षा के रूप में एक अभिक्षमता परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार आयोजित की जाती है। इससे चयनित अभ्यर्थियों को क्षमता और प्रवृत्ति के अनुसार उपयुक्त पेशे का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। अब तक अभ्यर्थियों को तीन क्षेत्रों अर्थात् आथित्य सत्कार, निर्माण और ऑटोमोबाइल में प्रशिक्षित किया गया तथा कैरियर मार्गदर्शन और परामर्श केंद्र इस वर्ष इसमें 13 और पाठ्यक्रमों जोड़ने की योजना बना रहा है।
- यह अवधारणा है कि ऐसे युवक की पहचान करना जिसे गुणवत्तापूर्ण कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा सके जो बेरोजगार बनाम श्रमिक अपूर्णता के अंतराल को कम करने में सहायक होगा। सतत और स्थायी आय का स्रोत उपलब्ध कराने के अलावा यह कार्यक्रम कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी को कम करने में भी सहायक हैं।

Name of the Initiative -	Skill Development Program to impart vocational training to the tribal youth, Gadchiroli, Maharashtra
Nome of the Awardees –	(1) Shri Ranjit Kumar, IAS, District Collector, Gadchiroli, Maharashtra (2) Shri Abhishek Krishna (3) Shri T.S.K. Reddy (4) Shri P.V. Deshmane (5) Shri Y.S. Shende

Project in Brief

- In order to increase the employability of the youth largely dependent on primary sector, an initiative called as Skill Development Program was initiated on the guidelines of Prime Minister’s Counsel for Skill Development. The Career Guidance and Counseling Center in the district was formulated to regulate the program under the control of the District Skill Development Executive Committee. The District Collector is the chairperson of this committee.
- The unemployed/ underemployed youth undergo counseling at the village level which is followed by an entrance examination in form of an aptitude test and personal interview. This helps in determining a suitable trade as per the ability and inclination of the selected candidates. So far the candidates were trained into three domains viz. Hospitality, Construction and Automobile and this year onwards, the CGCC is planning to scale up for 13 more disciplines to add into cart.
- The concept is to identify the youth to whom quality skill development training could be imparted which would help to bridge up the unemployment vs. labour deficiency gap. Apart

विशेषताएं

- सलाहकारों के जरिए अत्यंत जमीनी स्तर पर कवरेज
- परीक्षा एवं साक्षात्कार के जरिए अभ्यर्थियों का चयन करना जो चयनित अभ्यर्थी के लिए उपयुक्त पेशे तथा ऐसे पेशे की बाजार मांग की पहचान कराने में सक्षम बनाती है।
- प्रशिक्षण और परिवहन प्रभार का वहन सीधे ही जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है जबकि भोजन और आवास का व्यय संस्थान द्वारा किया जाता है जिसकी प्रतिपूर्ति प्रशिक्षण संपन्न होने के बाद की जाती है। अभ्यर्थी को कोई व्यय नहीं करना होता है।
- अपेक्षित लचीलेपन और आवृत्ति पर विचार करते हुए आवश्यकताओं का समायोजन करने के लिए प्रत्येक माह नया बैच आरंभ किया जाता है।
- पिछले तीन वर्षों में प्रशिक्षित 88% अभ्यर्थियों का सफलतापूर्वक रोजगार प्राप्त हुआ जिनमें से अधिकांश प्रमुख शहरों और उद्योगों में हैं।
- अभ्यर्थी वर्ष भर रोजगार की उपलब्धता सहित औसतन प्रति माह 8500/- रूपए अर्जित करते हैं।

प्रभाव

पिछले तीन वर्षों में इस कार्यक्रम ने कार्यक्रम में आने वाले अभ्यर्थियों की संख्या और रोजगार प्राप्ति के संदर्भ में आशाजनक सफलता प्रदर्शित की है। जिला कार्यकारी समिति ने इस पहल के क्षेत्र में आगामी वर्षों में 13 और पाठ्यक्रमों का विस्तार करने का निर्णय लिया है।

इस पहल के जरिए रोजगार प्राप्त करने में सफल रहे अभ्यर्थी अब इस कार्यक्रम के प्रसार में सहायता कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के पहुंच के संदर्भ में अत्यंत उच्च स्तर की अभिसारिता और अंतर-विभागीय समन्वय है।

इस पहल ने उद्योग की कतिपय श्रेष्ठ कंपनियों में रोजगार का अवसर सृजित किया है जो अन्यथा इस दूरदराज और जनजातीय जिला गढ़चिरौली के अभ्यर्थियों के लिए संभव नहीं था।

from providing consistent and sustainable source of income, the program is also assisting in reducing disguised unemployment in agriculture sector.

Highlights

- Higher grassroots coverage through counselors.
- Selection of candidates through examination and interview which enables to identify the trade that is suitable for the selected candidate as well as the market demand for such trade.
- Training and Transportation charges are directly borne by District administration while expenditure on food and accommodation is done by the institute which is reimbursed after completion of the training. There is no cost to the candidate.
- Considering the flexibility and frequency required, new batch is started to accommodate requirement every month.
- In past three years, 88% of the candidates, which were trained, have been successfully placed, many of them in major cities and industries.
- On an average, the candidate receives Rs. 8500/- per month along with a job availability for across the year.

Impact

In past three years, the program has shown the promising success in terms of number of candidates joining the program as well as the placements that has been secured. The District Executive Committee has decided to expand the scope of the initiative by adding 13 more courses in coming year.

The candidates who have succeeded in achieving placements through this initiative are now assisting the program publicity. There is a high degree of convergence and inter-department coordination in terms of outreach of the program.

पहल का नाम : इरविपेरूर ग्राम पंचायत - स्थानीय स्वशासन की सफल कहानी

संगठन का नाम : इरविपेरूर ग्राम पंचायत, कोझीमाला डाकघर, तिरुवल्ला, पतनमतिट्टा (जिला), केरल

परियोजना संक्षेप में

इस परियोजना ने इरविपेरूर पंचायत में ग्राम ज्ञान केंद्र, पर्यावरण ग्राम सभा, कचरा प्रबंधन, लघु जलापूर्ति स्कीम, आरोग्य सभा, जागृत समिति आदि से पूर्ण एक कागज रहित एवं आधुनिक कार्यालय का लक्ष्य प्राप्त किया।

विशेषताएं

- **कागज रहित कार्यालय**
 - (क) ऑनलाइन प्रमाणपत्र
 - (ख) कार्यालय अभिलेखों का डिजीटलीकरण
 - (ग) सेवा का अधिकार अधिनियम पर आधारित गुणवत्तापूर्ण सेवा
 - (घ) वायस और पाठ संदेश के जरिए नोटिस और सूचना
 - (ङ.) बैंकों के जरिए कर्मचारियों का वेतन तथा बोर्ड सदस्यों के मानदेय
 - (च) पांच मिनट के भीतर रिकार्ड और दस्तावेजों का पता लगाने के लिए व्यवस्थित रिकार्ड कक्ष
 - (छ) फाइल संचालन का पता लगाने तथा सूचना के लिए टच स्क्रीन की सुविधा
 - (ज) कार्यालय के सभी अनुभागों सहित फ्रंट ऑफिस को नेटवर्क युक्त बनाया गया
 - (झ) सूचना केरल मिशन (आईकेएम, एक सरकारी एजेंसी) द्वारा विकसित 12 साफ्टवेयरों की संस्थापना और अनुप्रयोग

Name of the Initiative: Eraviperoor Grama Panchayat -
Success Story of Local Self Governance

Name of the Organization - Eraviperoor Grama Panchayat,
Kozhimala P.O, Thiruvalla,
Pathanamthitta (Dist), Kerala State

Project in Brief

The project achieved a paperless and modern office at Eraviperoor Panchayat with a Village Knowledge Centre, Environment Gramasabha, waste management, a mini water supply scheme, Arogya Sabha, Jagratha Samithy, etc.

Highlights

1. Paperless Office

- (a) Online Certificates
- (b) Digitalization of Office records
- (c) Quality services based on Right to Service Act.
- (d) Notices and information through Voice and Text messages.
- (e) Salary of employees and honorarium of board members through bank.
- (f) Arranged record room to trace the records and documents within five minutes
- (g) Touch screen facility to trace the file movement and information
- (h) All sections of the office including Front Office networked
- (i) Installation and application of 12 softwares developed by Information Kerala Mission(IKM, a Government agency)

• **ग्राम ज्ञान केंद्र**

- क. संदर्भ पुस्तकालय
- ख. सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्कूली विद्यार्थियों का प्रशिक्षण
- ग. संस्कृत आदि पर कक्षाएं
- घ. गांव के इतिहास, संस्कृति और परम्परागत ज्ञान की निदेशिका तैयार करना

• **पर्यावरण ग्राम सभा**

- क. सभी वार्डों में विशेष ग्राम सभा
- ख. पर्यावरण मुद्दे और कचरा प्रबंधन संबंधी जागरूकता
- ग. उक्त मुद्दों पर ग्राम सभा ने कतिपय परियोजनाओं का सुझाव दिया
- घ. ग्राम सभा प्रतिभागियों को 20,000 पौधे वितरित किए गए।

• **कचरा प्रबंधन**

- क. बायो-गैस संयंत्र, केंचुआ - पाइप - रिंग खाद यूनिट का वितरण
- ख. प्लास्टिक पुनर्चक्रण यूनिट
- ग. प्लास्टिक रोड
- घ. खाद गड्ढा
- ङ. आधुनिक बूचड़खाना
- च. आधुनिक मछली बाजार
- छ. वार्ड समिति द्वारा पारिस्थितिकी को महत्व देना।

• **लघु जलापूर्ति योजना**

- क. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति योजनागत निधि से 8 स्कीमों को पूरा किया गया।
- ख. निधि के अंतर्गत 3 स्कीमों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत 2 स्कीमों लगभग संपन्न होने वाली हैं।

- **Village Knowledge Centre**
 - a. Reference library
 - b. Training for School Students on Civil Service and other competitive examinations
 - c. Classes on Sanskrit etc.
 - d. Preparing a directory of history , cultural and the traditional knowledge of the village.

- **Environment Gramasabha**
 - a. Special gramasabha in all wards
 - b. Agenda was awareness on environmental issues and waste management
 - c. Certain projects on the said issues suggested by the gramasabha
 - d. 20,000 seedlings were distributed to gramasabha participants

- **Waste Management**
 - a. Distribution of bio-gas plant, vermi-pipe-ring compost units
 - b. Plastic Recycling Unit
 - c. Plastic Road
 - d. Compost pit
 - e. Modern Slaughter House
 - f. Modern Fish Market
 - g. Ward committee giving importance to ecology

- **Mini Water Supply Scheme**
 - a. 8 Schemes were completed under SC/ST plan fund
 - b. 2 schemes under General fund and 2 scheme under SC/ST plan fund are about to complete.

- **आरोग्य सभा**
 - क. 8 केंद्रों में योग कक्षाएं, मालिश-योग जीवन शैली संबंधित बिमारियों का उपचार है।
 - ख. आयुष - प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में आयुर्वेद, होम्यो डिस्पेंसरी उप केंद्र तथा एक योग केंद्र शुरू किया गया।
 - ग. 105 बालिका विद्यार्थियों के लिए स्कूल कराटे कक्षाएं
 - घ. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का पुनरुद्धार
 - ङ. पीड़ा और प्रशामक उपचार
 - च. कैंसर के इलाज हेतु बीमा कवरेज
- **जागृत समिति**
 - क. महिलाओं और बच्चों को अपनी शिकायतों का समाधान करने हेतु पुलिस थाना अथवा न्यायालय जाने की आवश्यकता नहीं होती है।
 - ख. पिछले वर्ष 73 में से 68 मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान किया गया।

प्रभाव

इस पहल के माध्यम से हुए सकारात्मक बदलावों की लोगों ने प्रशंसा की तथा सर्वेक्षण ने यह दर्शाया कि सेवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। यह पंचायत के लोगों के मंगल और उत्तम आजिविका को सुनिश्चित करने हेतु सुशासन का एक प्रयोग है। प्रत्येक परियोजना के कार्यान्वयन के समापन से विकास के बेहतर परिणाम प्राप्त हुए।

- **Arogya Sabha**
 - a. Yoga Classes at 8 centers, message-yoga is remedy for life style disease
 - b. Ayush- Ayurveda, Homeo Dispensaries sub-centers and a yoga center started at Primary Health Centre Compound.
 - c. School Karate Classes for 105 girls students
 - d. Renovation of Primary Health Centre building
 - e. Pain and Palliative Care
 - f. Insurance coverage for Cancer treatment

- **Jagratha Samithy**
 - a. Women and children need not go to police station or court to get remedy on their complaints.
 - b. 68 of 73 complaints were amicably settled last year.

Impact

The positive changes brought about by the initiative are appreciated by the people and a survey shows the quality of the service has improved. It is an experiment in good governance to ensure the well being and good livelihood of the people of the panchayat. The completion of the implementation of each of the projects results the better growth.

पहल का नाम : नहर उपरीय सौर ऊर्जा संयंत्र - हरित और स्वच्छ ऊर्जा की ओर एक नया कदम

पुरस्कार विजेता का नाम : गुजरात राज्य विद्युत निगम लि.

परियोजना संक्षेप में

गुजरात राज्य सरकार ने तेजी से घटते ऊर्जा स्रोतों जैसे कोयला, तेल, गैस आदि के किफायती उपयोग की बढ़ती जरूरत तथा हरित और स्वच्छ ऊर्जा के महत्व के बारे में बढ़ती जागरूकता को ध्यान में रखते हुए सौर नीति - 2009 की शुरुआत की थी। यह परियोजना सौर ऊर्जा शक्ति के साथ जल शक्ति का दोहन करती है जबकि भूमि की बचत और वाष्पीकरण को कम करके जल का संरक्षण करती है।

विशेषताएं

- (क) जीएसईसीएल ने इस अद्भुत और नवीन विचार को कार्यान्वित करने की चुनौती को स्वीकार किया।
- (ख) परियोजना हेतु अपेक्षाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने के बाद इस स्थल का चयन किया गया था।
- (ग) एक प्रोटोटाइप ढांचा डिजाइन करके - नहर के निकट एक अलग स्थान पर कार्यान्वयन टीम के लिए अनिवार्य और महत्वपूर्ण सीख अनुभव हेतु संस्थापित किया गया।
- (घ) नहर की संरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित क्षमता और क्षरणरोधी क्षमताओं से युक्त विशेष ढांचे की संकल्पना की गई एवं डिजाइन और विनिर्माण किया गया।
- (ङ) नहर पानी सौर पैनलों के तापमान को कम रखने सहायक है; इससे सौर संयंत्र की दक्षता में और सुधार होता है तथा अत्यधिक बिजली उत्पादन प्राप्त होता है।
- (च) पारेषण हानि कम हुई फलस्वरूप ग्रिड मजबूत हुआ।
- (छ) संयंत्र की मानीटरिंग/आनलाइन दूरस्थ निगरानी के लिए नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीक का उपयोग।

Name of the Initiative - Canal Top Solar Power Plant-A New Direction to Green and Clean Energy

Name of the Awardees – Gujarat State Electricity Corporation Ltd. (GSECL)

Project in Brief –

Keeping in view the increasing need to economise use of fast depleting energy sources like coal, oil, gas etc., and increasing awareness about the importance of green and clean energy, Government of Gujarat introduced the Solar Policy – 2009. This project exploits Solar Urjashakti with Jalshakti while saving land and conserving water by reducing evaporation.

Highlights :

- a) GSECL took up the challenge to implement the novel & innovative idea.
- b) The site for the project was selected after scientific study of the requirements.
- c) A prototype structure was designed and installed at a separate site, very near to canal – essential and significant learning experience for the implementation team.
- d) Conceptualization, design and manufacturing of the special structure with required strength and corrosion protection capabilities, keeping safety of canal on priority.
- e) The canal water is instrumental in lowering the temperature of the solar panels; this further improves the efficiency of the solar plant and yields a higher electricity output.
- f) Minimization of the transmission loss leading to strengthening of the grid.
- g) Use of latest IT & technology for the monitoring/online remote monitoring of the plant.

- (ज) उत्पादन पर जल वाष्पीकरण के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक 10 किलोवाट का संयंत्र नहर के निकट, उसी स्थान पर स्थापित किया जा रहा है।
- (झ) पर्यावरण, वनस्पति एवं जीव जन्तुओं का संरक्षण
- (ञ) समुचित हरियाली सहित आस-पास के क्षेत्रों का विकास, जलीय जीवन के विकास को प्रोत्साहन।
- (ट) छह माह के भीतर सफल कार्यान्वयन

प्रभाव

- (क) एक प्रमुख परिणाम यह है कि मौजूदा अवसंरचना का उपयोग करके हरित ऊर्जा उत्पादन के लिए एक नई दिशा को खोला है जिसके अनेक लाभ हैं।
- (ख) 22 फरवरी, 2012 - अगस्त, 2014 (30 माह) की अवधि के दौरान 3935 मेगावाट हरित ऊर्जा का उत्पादन हुआ।
- (ग) 31 मार्च, 2014 तक कार्बन उत्सर्जन में लगभग 3771 टन की बचत हुई।
- (घ) प्रति वर्ष प्रति मेगावाट 9 मिलियन लीटर जल की बचत हुई।
- (ङ) हरियाली सहित आस-पास के क्षेत्रों का विकास
- (च) यह परियोजना पूरी तरह दोहराए जाने योग्य होने के कारण राज्य में मौजूदा नर्मदा के मुख्य नहर और शाखा नहर पर उच्चतर उत्पादन क्षमता वाली और परियोजनाओं की योजना बनाई जा रही है।
- (छ) कम से कम 10-15 व्यक्तियों - अकुशल, अर्द्धकुशल और कुशल व्यक्तियों के लिए रोजगार का अवसर जो नहर की लम्बाई पर निर्भर करता है।

- h) A 10 KW plant is being set up on land near the canal, at the same location, to study the impact of evaporating water on generation.
- i) Conservation of the environment, flora and fauna.
- j) Development of the surrounding areas with suitable greenery, encouragement to growth of aqua life.
- k) Successful commissioning within 6 months.

Impact

- a) One of the major outcomes has been opening of the new direction for green energy generation using existing infrastructure, with many advantages.
- b) Generation of 3935 MWh of green energy during the period 22nd February 2012-August 2014 (30 months)
- c) Carbon emission saved of aprox. 3771 Tonnes till 31st August, 2014.
- d) Saving of 9 million litres/MW of water/year.
- e) Development of surrounding area with greenery.
- f) The project being fully replicable, further projects with higher generation capacity are being planned in the State, on the existing Narmada Main as well as Branch canal.
- g) Employment opportunity for minimum 10-15 persons – unskilled, semi-skilled and skilled depending on length of canal.

